भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 259
उत्तर दिनांक 06.08.2025 को दिया गया

हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

*259. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या हरियाणा में गोरखपुर परमाणु विद्युत संयंत्र की प्रथम इकाई, जिसे वर्ष 2014 में अनुमोदित किया गया था, अभी भी केवल 74 प्रतिशत पूर्ण हो पाई है और इसके वर्ष 2028 तक ही कार्य शुरु करने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने इस विलंब के कारणों और ऊर्जा क्षमता और लागत वृद्धि पर इसके प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु अवसंरचना का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं के निर्धारित समय-सीमा में पूरा न होने के संबंध में कोई जवाबदेही निर्धारित की जाती है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

"हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र" के संबंध में श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 259 के भाग (क) से (घ), जिसका उत्तर दिनांक 06.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण

(क) गोरखपुर नाभिकीय विद्युत परियोजना में प्रत्येक 700 मेगावाट की दो जुड़वां-इकाइयाँ शामिल हैं अर्थात् जीएचएवीपी-1 व 2 (2X700 मेगावाट) और जीएचएवीपी-3 व 4 (2X700 मेगावाट)। सरकार द्वारा फरवरी 2014 में जीएचएवीपी-1 व 2 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई थी। वर्तमान में, जीएचएवीपी-1 व 2 निर्माणाधीन हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) हां। उत्खनन गतिविधियाँ वर्ष 2018 में शुरू हुईं। यह स्थल केवल मृदा वाला क्षेत्र है जहाँ कोई कठोर चट्टान नहीं है। अतः उत्खनन व भू-सुधार (जीआई) हेतु संहत मृदा सीमेंट मिश्रण की तकनीक अपनाई गई। इसके बाद आधार स्तम्भों का निर्माण कार्य और उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया।

हालांकि पुष्टिकरण भू-तकनीकी परीक्षणों में मृदा स्तर में कुछ स्थानों पर कमजोर परतें पाई गईं। इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रतिष्ठित सलाहकार की सेवाएं ली गईं जिसने व्यापक जाँच कर, सुधार हेतु सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों की वर्तमान में नियामक प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगा, जिसके कारण नाभिकीय आईलैंड के निर्माण में देरी हुई।

हालाँकि, उपकरणों, प्रमुख ईपीसी पैकेजों और अन्य मुख्य संयंत्र भवन के निर्माण का आवंटन कार्य आगे बढ़ता रहा।

(ग) परियोजना गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए, विनिर्माण में अधिक समय लगने वाले उपकरणों का अग्रिम प्रापण शुरू कर दिया गया है। तदनुसार, प्रमुख उपकरणों का कार्यादेश दे दिया गया है, जिनमें से कुछ स्थल पर प्राप्त भी हो चुके हैं। सभी प्रमुख उपकरण और कार्य पैकेज जैसे मुख्य संयंत्र सिविल कार्य, परमाणु पाइपिंग, टर्बाइन आइलैंड, आईडीसीटी आदि आवंटित कर दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना गतिविधियों की बहुस्तरीय निगरानी, बाधाओं की समय पर पहचान और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना, विक्रेताओं/ठेकेदारों के साथ लगातार बैठकें और निर्माण गतिविधियों का पुनः अनुक्रमण व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं।

(घ) जब तक स्थल विशिष्ट भू-सुधार कार्य पूर्ण नहीं हो जाते और नियामक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, तब तक मुख्य नाभिकीय आइलैंड में पूर्ण रूप से निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा। फिलहाल परिधीय भवनों/संरचनाओं का कार्य जारी है। निर्माण के दौरान मिट्टी की स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव के कारण मुख्य रूप से देरी हुई है।

*****